LOK SABHA

Thursday, 14th November, 1957

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

सीमेंट का कोटा

***१२८. श्री बिभूति मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से राज्य सीमेंट के अपने पूरे कोटे को कारखानों से नहीं उठा पाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो १९५५–५६ और १९५६–५७ में किन-किन राज्यों ने सीमेंट का अपना पूरा कोटा नहीं लिया; और

(ग) न लिये गये सीमेंट के इस कोटे को सरकार ने राज्यों को किस आधार पर पुन: वितरित किया है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) कारखानों को आर्डर देने और अलाट किये गये कोटों का माल उठाने में देर होने की कुछ शिकायतें तो आई हैं लेकिन ऐसा कोई खास मामले देखने में नही आये हैं जिन में राज्यों ने अलाट किये गये पूरे कोटे का माल न उठाया हो ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

श्री बिभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने सीमेंट का बंटवारा हर स्टेट पापुलेशन के के बेसिस पर रक्खा है या उन की आवश्यकता के अनुसार रक्खा है ?

श्री मनुभाई शाह : उन की आवश्यकता और भूतकाल में वे कितना कोटा उठा रहे थे, उस मिकदार को देखते हुए रक्खा गया है ।

श्री बिभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि इस में सरकार ने पबलिक सैक्टर में कितना रक्खा है और प्राइवेट सैक्टर के लिये कितना रक्खा है ?

श्री मनुभाई शाह : वह इस तरीके से नहीं बांटा जाता है बल्कि वह प्रोजैक्ट वाइज बांटा जाता है और ऐसी कोशिश की जाती है कि सब को कुछ मिले। पबलिक सैक्टर में वह तकरीबन ७० परसेन्ट डिस्ट्रिब्यूट हो गया है ।

श्री बिभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि आम जनता के खर्च के लिये सरकार कितने परसंट सीमेंट का बटवारा करती है ?

श्री मनुभाई शाह : उस की परसेंटेज नही है लेकिन हर एक स्टेट को कन्ज्यूमर्स कोटा दिया गया है और सब मिला कर वह करीब सालाना ६, ७ लाख का हो जाता है।

डा० राम सुभग सिंह : क्या सरकार इस बात का पता लगाती है कि जो सीमेंट की दरख्वास्तें कुंएं वगैरह बनाने के लिये जेठ और असाढ़ के महीनों में दी जाती हैं उन पर आज तक भी विचार नहीं हुआ है ?

श्री मनुभाई शाह : जहां तक कुंएं वगैराह बनाने का ताल्लुक है, स्टेट गवर्नमेंट्स उनको देती हैं लेकिन हम यह कोशिश करते हैं कि एग्रीकल्चरिस्ट्स को ज्यादा प्रीफ़ेंस दिया जाय और इस किस्म की हिदायत सब स्टेट् गवर्नमेंट्स को दे दी गई है

डा० राम सुभग सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन हिदायतों का पालन भी होता है?

श्री मनुभाई शाह : आम तौर पर पालन होता है लेकिन अगर कोई ऐसी तकलीफ कहीं पर हुई हो तो मेम्बर साहबान हमारे नोटिस में लायें और हम जरूर उन के बारे में जांच करेंगे ।

Shri B. S. Murthy: May I know on what basis the quota for consumers is allotted?

Shri Manubhai Shah: As I said, the basis is neither population nor the quantum of production, but the past off-take, and also the public sector projects and the high development projects in each State.

Shri Tangamani: For the Madras State, the monthly quota allotted is 26,000 tons. In view of the fact that more than 70,000 tons are being produced in Madras State, may I know whether the quota for Madras will be increased?

Shri Manubhai Shah: Quotas are not distributed according to the location of factories. If that were the consideration, perhaps, a few States will take away the entire quota of cement production in this country. The quotas are fixed on the basis of the past off-take of the States and the different priorities.

Shri Damani: The quotas allotted to dealers often go into undesirable channels, and in this way, they get higher prices May I know whether such cases have been detected, and if so, what action has been taken so far?

Shri Manubhai Shah: As the House is aware, cement control is a statutory control. And if anybody indulges in any practice which is not correct under the law, the State Governments concerned do take action. Actually, every release is against a permit.

Shri R. Ramanathan Chettiar: May I know whether it has been brought to the notice of Government that some States are experiencing difficulties in regard to cement for their various State projects, and they have made representations to the Government of India and yet the difficulties have not been remedied so far?

Shri Manubhai Shah: That is generally true, because today the demand for cement is much higher than the production. And every State wants more than what we can give. But as the production is rising, the relief given to every State is much larger than before.

Roads in Nepal

†

*129. **Shri Bibhuti Mishra:**
Shri Shree Narayan Das:
Shri Radha Raman:
Shri Raghunath Singh:

Will the **Prime Minister** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1650 on the 10th September, 1957, and state:

(a) whether the proposal to have an agreement between the Governments of Nepal, India and U.S.A. for construction of some roads in Nepal has been finalised;

(b) the nature of the agreement concluded;

(c) whether any specific plan and programme for road construction have been drawn up; and

(d) if so, their important features?

The Deputy Minister of External Affairs (Shrimati Lakshmi Menon): (a) No, Sir.

(b) to (d). Do not arise.

श्री विभूति मिश्र : क्या यह सही नही है कि अभी हाल में भारतवर्ष, अमरीका और नैपाल के साथ मिल कर के वहां पर सड़कें बनाने के लिये कार्यवाही की जा रही है ?

Shrimati Lakshmi Menon: The hon. Member has asked about the finalising of the agreement. The agreement is not finalised yet.

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि एग्रीमेंट कब तक फाइनैलाइज होगा ?

अध्यक्ष महोदय : जल्दी होगा ।